

उत्तराखण्ड विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य विधानसभा में 5,013 करोड़ रुपए का [अनुपूरक बजट \(Supplementary Budget\)](#) प्रस्तुत किया।

मुख्य बिंदु

- उत्तराखण्ड कारागार एवं सुधार सेवाएँ अधिनियम, 2024 तथा [ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950](#) में संशोधन भी प्रस्तुत किया गया।
 - अनुपूरक बजट में केंद्र पोषति योजनाओं के लिये 1,532 करोड़ रुपए तथा बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये 273 करोड़ रुपए शामिल थे।
 - राज्य में बड़े निर्माण कार्यों के लिये कुल 749 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
 - [टहिरी झील विकास](#) के लिये 50 करोड़ रुपए, [गौ सदन निर्माण](#) के लिये 32 करोड़ रुपए, नर्सिंग कॉलेजों के लिये 25 करोड़ रुपए तथा डग्री कॉलेजों के निर्माण के लिये 14 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
- उत्तराखण्ड कारागार एवं सुधार सेवाएँ अधिनियम, 2024 का उद्देश्य केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कई पुराने अधिनियमों को नरिस्त करने के बाद [राज्य के कारागार कानूनों को अद्यतन](#) करना है। यह अधिनियम केंद्रियों के प्रबंधन और पुनर्वास से संबंधित है।
- राज्य सरकार ने [नगरपालिका कषेत्रों](#) के वसितार और संबंधित भूमि विवादों से उत्पन्न मुद्दों के समाधान के लिये [ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम](#) में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950

- यह भारत में ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने वाला पहला महत्त्वपूर्ण कानून था।
- इस सुधार का मुख्य लक्ष्य ज़मींदारों, जागीरदारों और इनामदारों जैसे [बच्चौलियों](#) को हटाना था, जो काश्तकारों का शोषण कर रहे थे।
- इस सुधार का उद्देश्य [भूमिका स्वामित्व सीधे भूमिधारकों या कृषकों को हस्तांतरित करके उन्हें मज़बूत बनाना भी था।](#)